



श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

राष्ट्राय स्वाहा,
इदं राष्ट्राय, इदं न मम

ऑपरेशन सिंदूर की गूंज के साथ भारत की शौर्य गाथा में एक नया अध्याय जुड़ा है



आपका संकल्प- हमारा विश्वास

वीर धरा राजस्थान माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन करती है



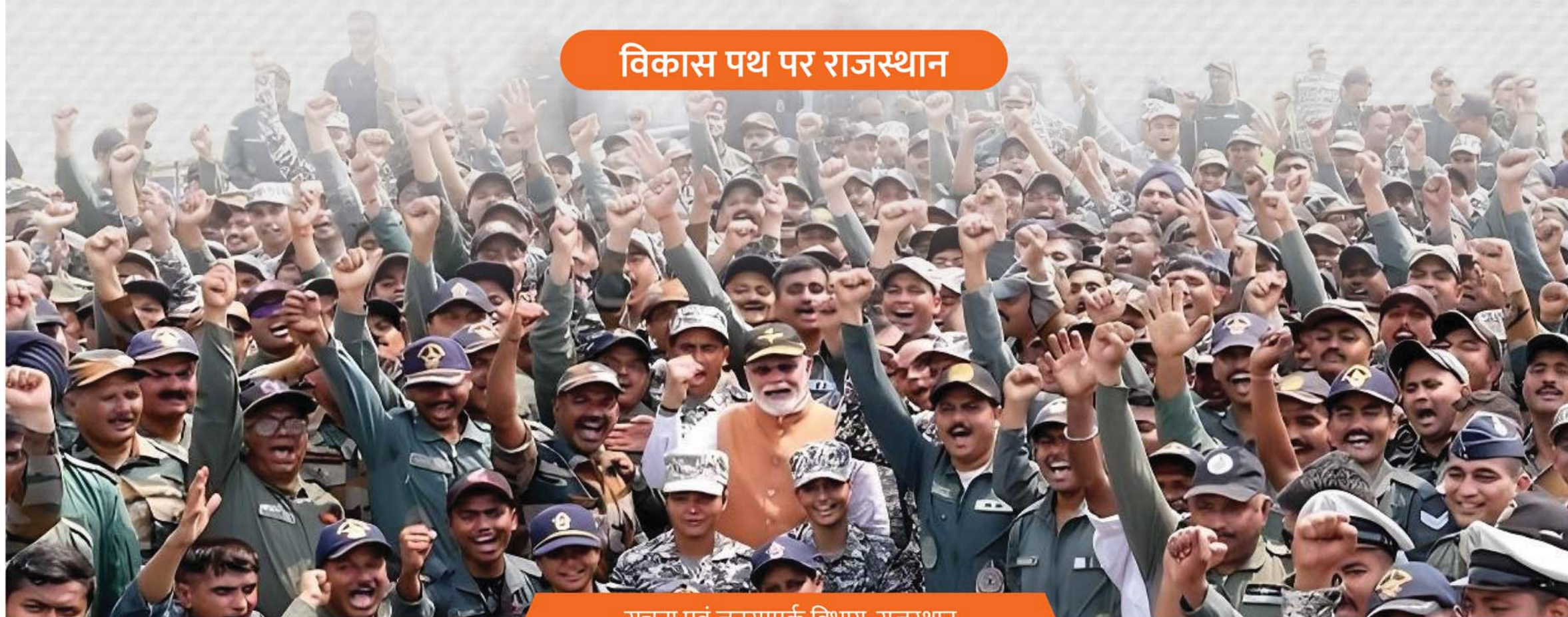
प्रदेशवासियों को 26 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों तथा
देश को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों की सौगात

मुख्य अतिथि
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

22 मई, 2025 | प्रातः 10:30 बजे | स्थान - पलाना, बीकानेर

आप सादर आमंत्रित है

विकास पथ पर राजस्थान



सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोन:- 226422, 226423 फैक्स:- 02973-226424

वर्ष: 20

संख्या: 42

प्रभात

जालोर, मंगलवार 20 मई, 2025

पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24

पृष्ठ 8

मूल्य 2.50 रु.

राहुल गाँधी ने जयराम रमेश को चुप कराया

‘यह समय नहीं है, थरूर के खिलाफ बयानबाजी का, जब थरूर भारत के प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व कर रहे हैं, भारत का पक्ष विदेश में समझाने-सुनाने के लिए’

-रेणु मि्तल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मई। राहुल गांधी ने शशि थरूर को लेकर कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी संघर्ष पर फिलहाल विराम लगा दिया है। उन्होंने पार्टी के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे थरूर के खिलाफ बयानबाजी बंद करें, खासकर तब, जब शशि थरूर अंतरराष्ट्रीय दौरों पर राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।

सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने स्पष्ट किया है कि इस समय पार्टी के आंतरिक मतभेद उजागर करना सही नहीं होगा, इससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर ऐसा लगेगा कि कांग्रेस “तुच्छ राजनीति” कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इस मुद्दे को प्रतिनिधिमंडल के लौटने के बाद निपटारा जाएगा।

कांग्रेस के भीतर यह जर्बदस्त धारणा है कि जयराम रमेश ने मीडिया विभाग के प्रमुख पद का फायदा उठाते हुए अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर यह बयान दे दिया कि सरकार को कांग्रेस की ओर से भेजे गए चार नामों को राहुल गांधी

■ राहुल ने जयराम से यह भी कहा, कि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर, यह मैसेज नहीं जाना चाहिए कि कांग्रेस अपनी अन्दरूनी लड़ाई में उलझी है, जबकि मसला देश की सुरक्षा व पाकिस्तान के आतंकवाद का है, अतः पार्टी के अन्दरूनी राजनीति के मामले बाद में निपटाये जा सकते हैं जब प्रतिनिधि मण्डल विदेश से लौट आये।

■ कांग्रेस का एक धड़ा यह भी मान रहा है, कि पार्टी को इस लफड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए, कि भारत सरकार किस-किस को प्रतिनिधि मण्डल में शामिल करना चाहती है।

■ जयराम रमेश शायद यह कहकर, कि राहुल गाँधी ने चार नाम चुने हैं, जो प्रतिनिधि मण्डल में पार्टी की ओर से जायेंगे, बेवजह राहुल को इस विवाद में डाल दिया।

■ अब, जयराम रमेश अपनी सफाई में यह कह रहे हैं कि संसदीय मामलों के मंत्री रिजिजू ने उनसे वो चार नाम मांगे, जिन्हें कांग्रेस प्रतिनिधि मण्डल में शामिल कराना चाहती है, इसलिए उन्होंने चार नाम भेजे थे। पर, रिजिजू ने इस बात से इन्कार किया कि उन्होंने कांग्रेस से चार नाम मांगे थे।

■ दूसरी ओर शशि थरूर व मनीष तिवारी ने भी अपनी ओर से स्पष्ट किया कि वे प्रतिनिधि मण्डल में शामिल होंगे, अगर सरकार उन्हें आमंत्रित करती है।

■ यह भी उल्लेखनीय है कि गुलाम नबी आज़ाद का नाम भी शामिल किया गया है, सरकार की ओर से प्रतिनिधि मण्डल में, हालांकि, वे अब कांग्रेस में नहीं हैं।

ने मंजुरी दी है।

दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने

उन चार नामों में से तीन को खारिज कर

दिया और केवल आनंद शर्मा को स्वीकार

किया। इसके अलावा, उन्होंने शशि थरूर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कॉलेज शिक्षकों का रिटायरमेंट भी 65 साल में क्यों नहीं हो-हाईकोर्ट

जयपुर, 19 मई। राजस्थान हाई कोर्ट ने पूछा है कि मैडिकल शिक्षकों की तरह कॉलेज शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल क्यों न कर दी जाए। हाई कोर्ट ने इस बारे में प्रमुख बिधि सचिव, प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और यूजीसी सहित अन्य को

■ केन्द्र सरकार, यूजीसी, मेडिकल शिक्षक तथा डेढ़ दर्जन राज्यों में शिक्षकों की रिटायरमेंट आयु 65 वर्ष की जा चुकी है।

नोटिस भेजकर जवाब माँगा है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने ये आदेश डॉ. विश्राम लाल बैरवा और अशोक कुमार अग्रवाल सहित, अन्य की याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता सुप्रिय और अक्षय दत्त शर्मा ने अदालत को बताया कि केन्द्र सरकार और यूजीसी कॉलेज शिक्षकों की रिटायरमेंट उम्र 65 साल करने का प्रावधान कर चुके हैं। प्रदेश में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गैर सरकारी सदस्यों के बिना स्कूल फीस रिविज़न कमेटी की सुनवाई

जयपुर, 19 मई। स्कूल फीस से जुड़े विवादों की सुनवाई को लेकर रिवीजन कमेटी नहीं बनने से जुड़े मामले में शिक्षा विभाग की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया गया है। मामले में अदालत मंगलवार की सुनवाई करेगी।

शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल की ओर से पेश शपथ पत्र में कहा गया है कि कमेटी के गैर सरकारी सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं और नियुक्ति राज्य सरकार को करनी है। वहीं, आरटीआई अधिनियम में कमेटी के कोरम का भी कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में रिवीजन

■ शिक्षा सचिव ने हाईकोर्ट से कहा कि राज्य सरकार ने गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है। अब गैर सरकारी सदस्यों के बिना 26 मई से सुनवाई शुरू होगी।

प्रार्थना पत्रों के लॉबिंग प्रकरणों को देखते हुए इन गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार नहीं कर 26 मई से इन मामलों की सुनवाई की जाएगी।

दरअसल भारतीय विद्या भवन विद्याश्रम की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता स्कूल की फीस निर्धारण को लेकर स्कूल फीस कमेटी ने निर्णय लिया था। इस कमेटी के आदेश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रिलायंस ने एशिया का वर्ष 2025 का सबसे बड़ा अन्तरराष्ट्रीय ऋण प्राप्त किया

इस ऋण का पहला भाग 2.43 बिलियन डॉलर का है, तथा दूसरा भाग 67.7 बिलियन जापानी मुद्रा येन का है

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 19 मई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) ने 2.9 बिलियन डॉलर की ऐतिहासिक डुएल करैसी सिंडिकेटेड लोन डील हासिल की है, यह 2025 में एशिया की सबसे बड़ी डील है और पिछले दो वर्षों में किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा लिया गया यह सबसे बड़ा कर्ज है। यह वित्तीय सौदा दो भागों में विभाजित है: एक भाग में 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर और दूसरे भाग में 67.7 बिलियन (लगभग 462 मिलियन डॉलर) जापानी येन। विश्व की कुल 55 देशों के बैंकों ने इसमें भाग लिया, जिससे यह वर्ष का एशिया का सबसे बड़ा ऋण देने वाला संघ बन गया।

यह डील केवल एक वित्तीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह आरआईएल की वित्तीय ताकत और वैश्विक बाजारों में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा पर एक ठोस विश्वास की मुहर है। बढ़ती ब्याज दरों, भू-राजनीतिक तनाव और सीमित पूंजी

■ यह ऋण देने के लिए 55 अन्तरराष्ट्रीय स्तर के बैंक मिले और इस ऋण के लिए फायनैस का इन्तजाम किया।

■ यह ऋण एशिया का इस वर्ष का सबसे बड़ा ऋण है।

■ हालांकि, इस वर्ष एशिया की लगभग सभी बड़ी कम्पनियां और बैंक ऋण लेने व देने में काफी कतरा रहे हैं, अतः यह विशेष रूप से सराहनीय है, कि फायनैशियल दृष्टि से इस मायूस से वातावरण में भी रिलायंस ने इतना बड़ा ऋण लेकर, मायूसी के वातावरण में छेद कर दिया है।

के दौर में इतना बड़ा लोन हासिल करना रिलायंस की बेहतरीन क्रेडिट प्रोफाइल और वैश्वक आकर्षण को दर्शाता है। इस विश्वास के मूल में रिलायंस का विविधतापूर्ण मॉडल है, जो ऊर्जा, पेट्रोकैमिकल्स, टैलिकॉम (जियो), रिटेल, डिजिटल सेवाएं और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र में रिलायंस अग्रणी है, जिससे एक संतुलित पोर्टफोलियो बनता है, जो किसी एक क्षेत्र में आए उतार-चढ़ाव से कंपनी

को बचाता है। यही विविधता निवेशकों को दीर्घकालिक आय और स्थिरता के प्रति आश्वासन देती है। इस विश्वास को और मजबूती मिलती है रिलायंस की इन्वेस्टमेंट-ग्रेड क्रेडिट रेटिंग्स से, जो भारत की संप्रभु रेटिंग से भी ऊपर है। मूडीज ने आरआईएल को बीएए2 और फिच ने बीबीबी रेटिंग दी है, दोनों ही भारत से एक स्तर ऊपर हैं। उभरते बाजारों की कंपनियों में यह दुर्लभ उपलब्धि है, जो कंपनी की

को बचाता है। यही विविधता निवेशकों को दीर्घकालिक आय और स्थिरता के प्रति आश्वासन देती है।

इस विश्वास को और मजबूती मिलती है रिलायंस की इन्वेस्टमेंट-ग्रेड क्रेडिट रेटिंग्स से, जो भारत की संप्रभु रेटिंग से भी ऊपर है। मूडीज ने आरआईएल को बीएए2 और फिच ने बीबीबी रेटिंग दी है, दोनों ही भारत से एक स्तर ऊपर हैं। उभरते बाजारों की कंपनियों में यह दुर्लभ उपलब्धि है, जो कंपनी की

सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मजबूत पूंजी प्रवाह और अनुशासित वित्तीय प्रबंधन को दर्शाती है।

यह हाई रेटिंग रिलायंस को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी देती है। इससे पूंजी तक आसान पहुंच मिलती है, जो ग्रीन एनर्जी और 5जी बेसी परियोजनाओं के लिए बेहद अहम है। वित्तीय संस्थान उन कंपनियों को ऋण देना पसंद करते हैं, जिनका दृष्टिकोण स्थिर हो और भुगतान का इतिहास मजबूत हो, रिलायंस की ऐसी ही छवि है।

इस ऋण की डुएल करैसी संरचना आरआईएल की परिपक्व वित्तीय रणनीति को दर्शाती है। विभिन्न मुद्राओं में ऋण को विभाजित करना मुद्रा विनिमय दरों की अस्थिरता से बचाव, उधारी लागत में कमी और विविध नकदी स्रोतों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। विशेष रूप से, येन मुद्रा का होना यह दर्शाता है कि जापानी निवेशक भारतीय कॉर्पोरेट्स को ऋण देने में रुचि दिखा रहे हैं और रिलायंस बहु-विनियोग आधारों से पूंजी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विदेश मंत्री के वक्तव्य ने प्र.मंत्री मोदी को अटपटी स्थिति में डाला

- जाल खंबाता -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 19 मई। सुरक्षा संबंधी एक बहुत बड़ी गलती, जिसमें विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर लिप्त हैं, के रहस्योद्घाटन के बाद एक बड़ा राजनैतिक तूफान खड़ा हो गया है। बताया जाता है कि जयशंकर ने पाकिस्तान को उसके आतंकी ठिकानों पर भारत की स्ट्राइक से जुड़ी अतिसंवेदनशील कार्यवाही की जानकारी दी दी थी। इस रहस्योद्घाटन के बाद, राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ तो इसकी कड़ी आलोचना कर ही रहे हैं, इससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर भी दबाव बढ़ गया है। प्रधानमंत्री, विदेश नीति की इस नाकामी पर आक्रोश और आलोचनाओं से घिर गये हैं।

वरिष्ठ राजनयिकों और गुप्तचर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, डॉ. जयशंकर के मीडिया को दिये गये इस बयान, कि भारत की आतंकी-विरोधी कार्यवाही की अग्रिम सूचना पाकिस्तान को दे दी गई थी, ने इस सामरिक लोकेस के बारे में गंभीर चिन्ताएं खड़ी कर दी हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि हो सकता है कि इस अभूतपूर्व कदम से, असावधानीवश,

विदेश मंत्री ने मीडिया के समक्ष कहा कि भारत ने पाकिस्तान को आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन (ऑपरेशन सिन्दूर) के बारे में पहले ही बता दिया था

हाफिज़ सईद और मसूद अजहर जैसे प्रमुख आतंकी आकाओं को इस सटीक हमले से बचने का समय मिल गया हो और ऑपरेशन सिंदूर नामक इस मिशन के असली उद्देश्य को क्षति पहुंची हो।

एक शीर्ष विदेश नीति विश्लेषक ने कहा, “यह मात्र एक राजनयिक गलत कदम नहीं है, यह निर्णय लेने में की गई एक बेहद गंभीर गलती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।”

उन्होंने आगे कहा, “एक सुनियोजित सैन्य कार्यवाही की जानकारी आतंकियों को पनाह और संरक्षण देने वाले देश को दे देने से सैन्य कार्यवाही का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है तथा इस कदम के पीछे के रणनीतिक इरादे के बारे में प्रश्न खड़े होते हैं।

पूर्व विदेश मंत्री यशवन्त सिन्हा ने राजनैतिक मोर्चा संभालते हुए, सर्वोच्च स्तर

■ विदेश मंत्री के इस वक्तव्य से कई सवाल उठते हैं। क्या इस सूचना ने आतंकवादियों के संगठनों को अपने आतंकवादी शिविर छोड़ कर अन्यत्र चले जाने का मौका दे दिया। और इसीलिए हाफिज़ सईद व मसूद अज़हर बच निकले।

■ पूर्व विदेश मंत्री यशवन्त सिन्हा सबसे ज्यादा सक्रिय रहे, प्र.मंत्री को इस मुद्दे पर कठघरे में खड़ा करने में।

■ यहां तक कहा जा रहा है, कि विदेश मंत्रालय की इस त्रुटि ने मोदी सरकार की विदेश नीति की कमज़ोरियों को उजागर कर दिया है, और ऑपरेशन सिन्दूर की सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, तो विदेश नीति का “फेलियर”, भारत के पक्ष में कोई भी देश, सिवाय रूस के, खड़ा नजर नहीं आया।

■ साथ ही ट्रम्प के इस दावे ने, कि उसने मध्यस्थता करके व व्यापारिक हितों का तकाजा करके दोनों देशों के बीच ‘सौज फायर’ करवाया, भारत की व मोदी की मजबूत छवि पर, ग्रहण सा लगा दिया था, और विदेश मंत्रालय इस छवि को अभी तक पूर्णतया साफ नहीं कर पाया है।

पर जवाबदेही की मांग की है। एक इंटरव्यू में

उन्होंने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को खामोशी पर प्रश्न खड़े किये हैं तथा कहा

है कि जनता सुस्पष्ट स्पष्टीकरण की हकदार है। सिन्हा ने कहा, “यह केवल जयशंकर की चूक नहीं है, यह राष्ट्र-हित की रक्षा करने के

मामले में नेतृत्व की असफलता है।”

भाजपा तथा उसकी वैचारिक मार्गदर्शक संस्था आर एस एस के अंदरूनी सूत्र भी बढ़ते

जा रहे आंतरिक असंतोष की पुष्टि कर रहे हैं। भगवा खेम के अनेक लोगों का मानना है कि मोदी की मजबूत नेता की छवि पर इस विदेश नीति-कुप्रबन्धन की काली छाया पड़ी है। यह आलोचना इसलिए और प्रबल हुई है, क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने एयर स्ट्राइक के बाद, अप्रत्याशित रूप से युद्ध विराम के लिए मध्यस्थता करने का दावा किया, और प्रधानमंत्री ने उनके दावे को निर्यातित करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।

भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने नामोल्लेख न करने की शर्त पर बताया, “ट्रम्प के हस्तक्षेप तथा उनके प्रचार से भारत की छवि, उसकी अपनी क्षेत्रीय लड़ाई में गौण हो गई। -- यह एक कूटनीतिक लज्जा की बात थी तथा प्रधानमंत्री को इसे पूरी सख्ती से रोकना चाहिए।”

विपक्षी नेताओं ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए, मोदी की विदेश नीति को प्रतिक्रियाशील एवं असंगत बताया है। कांग्रेस सुप्रिया श्रीनेत ने इस प्रकरण को “कूटनीति एवं नेतृत्व की असफलता” बताया है तथा भारत के पिछले वर्ष की राष्ट्रीय सुरक्षा की कार्यवाहियों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है।

राजनैतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि निर्यातित करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया।

इस विवाद के परिणामस्वरूप, ऑपरेशन सिंदूर के संचालन तथा उसमें विदेश मंत्रालय की भूमिका की संसदीय जांच की मांग जोर पकड़ती जा रही है। लोगों का छवि, उसकी अपनी क्षेत्रीय लड़ाई में गौण हो गई। -- यह एक कूटनीतिक लज्जा की बात थी तथा प्रधानमंत्री को इसे पूरी सख्ती से रोकना चाहिए।”

विदेश नीति से जुड़े हैं।

